उड़ीसा राज्य और अन्य

बनाम

मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 653/2006)

4 फ़रवरी 2008

[डॉ अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226:

सरकारी अनुबंध - निविदाएं - न्यायिक समीक्षा - स्कोप - इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (आईडीसीओएल) ने तकनीकी बोलियां आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया - तीन में से दो पार्टियों की बोलियां सीमा पर खारिज कर दी गईं - तीसरे पक्ष का चयन - असफल पार्टियों द्वारा रिट याचिकाएं - उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई। जिसमें माना गया कि चयनित पार्टी की बोली का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया था - अपील पर, माना गया: उच्च न्यायालय ने बाहरी सामग्रियों पर भरोसा किया और निराधार निष्कर्ष पर पहुंचा - इसलिए, मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया जाना चाहिए था - लेकिन इस पर विचार करते हुए विज्ञापन 5 साल पहले जारी किया गया था और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों, अपीलों के आधार पर उपयुक्त निर्देशों

के साथ निपटारा किया गया - निर्देश जारी किए गए कि तीनों पार्टियों की तकनीकी बोलियों को वैध माना जाए - पार्टियों को संशोधित वित्तीय बोलियां जमा करने की अनुमति दी गई - आईडीसीओएल की अधिकृत समिति विचार करेगी तकनीकी बोलियाँ और वित्तीय बोलियाँ, विज्ञापन के मापदंडों, एनआईटी और राज्य के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए - अधिकारियों की दुर्भावना और उनके कथित पक्षपात के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों और निष्कर्षों को खारिज कर दिया गया।

उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आईडीसीओएल) ने संयुक्त उद्यम में क्रोमाइट जमा परियोजना के विकास के लिए तकनीकी बोलियां आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया। तीन में से दो पार्टियों अर्थात वीजा और टिस्को की बोलियाँ शुरुआत में ही खारिज कर दी गईं। तीसरा पक्ष, अर्थात. जिंदल का चयन किया गया। वीज़ा और टिस्को ने रिट याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसने यह कहते हुए अनुमति दी कि जिंदल की बोली का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया था और यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि तीनों पक्षों द्वारा पेश की गई बोलियों में से किस मामले में राज्य को अधिकतम लाभ हुआ था। जनता का ब्याज और राज्य का खजाना राज्य और आईडीसीओएल के

अधिकारियों की सद्भावना पर सवाल उठाने वाली कुछ टिप्पणियाँ करने के बाद, न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जिंदल का चयन करने के आईडीसीओएल के फैसले को रद्द कर दिया। अपीलकर्ताओं का तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने इस संबंध में किसी भी दलील के बिना विभिन्न अप्रासंगिक और असंगत सामग्रियों को ध्यान में रखा और अगर जिंदल की बोली को स्वीकार किया जाना था तो गलत तरीके से मिलीभगत और राजस्व की हानि मान ली।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए माना:

1. उच्च न्यायालय के कुछ निष्कर्ष स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नहीं हैं। जहां तक जिंदल का सवाल है, पक्षपात से संबंधित टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से बिना किसी आधार के हैं। [पैरा 10] [368-सी]

2. केवल इस आधार पर कि उच्च न्यायालय ने बाहरी सामग्रियों पर भरोसा किया था और निराधार निष्कर्ष पर पहुंचा था, सामान्य स्थिति में इस न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया होता और उच्च न्यायालय से मामले पर फिर से विचार करने के लिए कहा होता। लेकिन समय बीतने और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विज्ञापन 2002 में जारी किया गया था और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर, अपीलों का निपटारा निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:

ए. इसे सभी की तकनीकी बोली माना जाएगा तीनों पक्ष वैध हैं;

बी. वित्तीय बोलियाँ लगभग पाँच वर्ष पहले प्रस्तुत की गई थीं, पार्टियों को तीन सप्ताह के भीतर संशोधित वित्तीय बोलियाँ प्रस्तुत करने की अनुमति देना उचित होगा।

सी. आईडीसीओएल की उपयुक्त और अधिकृत समिति विज्ञापन के मापदंडों, एनआईटी और राज्य के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए तकनीकी बोलियों और वित्तीय बोलियों पर विचार करेगी। [पैरा 11] [368-डी, ई, एफ, जी]

3. अधिकारियों की दुर्भावना और उनके कथित पक्षपात के बारे में टिप्पणियाँ और निष्कर्ष खारिज किये जाते हैं। [पैरा 13] [369-बी, सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 653/2006

डब्ल्यू.पी. में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांक 18.11.2004 के अंतिम निर्णय और आदेश से। (सी) क्रमांक 6798/2004

साथ में

2006 की सिविल अपील संख्या 654, 655, 671, 672 और 673

जी.ई. वाहनवती, सॉलिसिटर जनरल, बी.के. मोहंती, महाधिवक्ता (उड़ीसा), अरुण जेटली, के.के. वेणुगोपाल, डॉ. ए.एम. सिंघवी, श्याम दीवान, शांति भूषण, अशोक परीजा, टी.आर. अंधियारुजिना, आर.एफ. नरीमन, रजत रथ, सुमन कुकरेती, राज कुमार मेहता, ऋषि माहेश्वरी,

पी.एस. सुधीर, ऐनी मैथ्यू, शैली भसीन माहेश्वरी, संजीव के कपूर, विशाल गुप्ता, विक्रम बजाज, कुमार मिहिर, अविनाश मेनन (एम/एस खेतान एंड कंपनी के लिए), आर.एन. उपस्थित पक्षों के लिए करंजावाला, गोपाल जैन, अखिल सिब्बल, नंदिनी गोरे, प्राची गोयल और माणिक करंजावाला।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे द्वारा सुनाया गया।

1. इन अपीलों में चुनौती उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले को है, जिसमें वीज़ा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (संक्षेप में 'वीज़ा') और एक अन्य (रिट याचिका (सी)) द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई है।) क्रमांक 5128 ऑफ़ 2004) और मेसर्स। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में 'टिस्को') (रिट याचिका (सी) संख्या 6798, 2004)। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने माना कि वीज़ा और टिस्को की तकनीकी बोलियों को पात्रता चिंतित विज्ञापन. यह भी माना गया कि जिंदल स्ट्रिप लिमिटेड (संक्षेप में 'जिंदल' की) बोलियों का मूल्यांकन और मूल्यांकन कभी भी निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया था। यह जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि तीनों दलों द्वारा पेश की गई बोलियों में से कौन सी बोली राज्य को बी सार्वजनिक हित और राज्य के खजाने के मामले में अधिकतम लाभ देगी। कुछ अन्य टिप्पणियाँ उड़ीसा राज्य और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (संक्षेप में 'आईडीसीओएल') के अधिकारियों की प्रामाणिकता पर

सवाल उठाते हुए की गईं। यह माना गया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाना था क्योंकि संबंधित परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में जिंदल का चयन ठीक से नहीं किया गया था। इसलिए जिंदल को चुनने का आईडीसीओएल का निर्णय सी नहीं हो सकता, बनाए रखा गया और अलग रखा गया।

2. यह नोट किया गया था कि संबंधित पक्षों की बोली डी पर नए मूल्यांकन और योग्यता के गठन के लिए मामले को आईडीसीओएल को भेजा जा सकता था, लेकिन इसे उचित नहीं समझा गया। यह भी नोट किया गया कि जिंदल ने स्टेनलेस स्टील उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था जिसे संयुक्त उद्यम भागीदार के प्रश्न पर निर्णय लेते समय एक प्रासंगिक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता था। हालाँकि, आईडीसीओएल को स्पष्ट शब्दों में यह बताने के लिए ई उद्देश्य के लिए एक नया विज्ञापन जारी करने का अवसर दिया गया था कि क्या वह राज्य में स्टेनलेस उद्योग स्थापित करना चाहता है या अन्य उद्योग जहां क्रोम को एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. विभिन्न पक्षों द्वारा पेश की गई तकनीकी बोलियां रिकॉर्ड में हैं। प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक, चार पार्टियों ने अपने प्रस्ताव जमा कर दिए थे, लेकिन बाद में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड इसे जारी नहीं रखना चाहता था।

4. वर्तमान अपीलें उड़ीसा राज्य, आईडीसीओएल और जिंदल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं से उत्पन्न हुई हैं।

5. श्री जी.ई. का प्राथमिक रुख वाहनवती, विद्वान सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। इसने विभिन्न अप्रासंगिक और अप्रासंगिक सामग्रियों को बिना किसी अनुरोध के ध्यान में रखा है। अगर जिंदल की बोली को स्वीकार किया गया तो इसमें मिलीभगत, राजस्व की हानि मानी गई है। यह समझ से परे है कि किस आधार पर निष्कर्ष निकाले गए, वह भी बिना किसी भौतिक आधार के ऐसा ही असर जिंदल के समर्पण का भी है. गौरतलब है कि जिंदल स्टील्स लिमिटेड को वर्तमान में जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। हालाँकि सुविधा के लिए इस फैसले में इसे 'जिंदल' के रूप में वर्णित किया जाएगा।

6. समान प्रभाव के लिए विद्वान परामर्श प्रस्तुत करना है आईडीसीओएल के लिए.

7. टिस्को और वीज़ा के विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष उचित हैं। न्यायिक समीक्षा के मापदंडों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि सरकार ने मामले के तथ्यों पर ध्यान दिए बिना सबसे यांत्रिक तरीके से मंजूरी दे दी। यह प्रस्तुत किया गया था कि जैसा कि उच्च

न्यायालय ने सही ठहराया है कि जिंदल आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करता है और इसलिए, उसकी बोली स्वीकार नहीं की जा सकती है।

8. टिस्को के विद्वान वकील द्वारा उजागर किए गए कारकों में से एक यह है कि सूचना विवरणिका और एनआईटी में "मूल्य संवर्धन" जैसी कुछ अस्पष्ट अभिव्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। ऐसी अनिश्चित स्थिति को देखते हुए टिस्को और वीज़ा द्वारा प्रस्तुत बोलियों को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता था और इसलिए उच्च न्यायालय ने इस मामले में उचित ही हस्तक्षेप किया है।

9. इस समय, संयुक्त उद्यम में टांगरपाड़ा क्रोमाइट डिपॉजिट के विकास के लिए प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी समिति की सिफारिशों को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

> "संयुक्त उद्यम में टांगरपाड़ा क्रोमाइट जमा के विकास के लिए प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी समिति की सिफारिशें संयुक्त उद्यम में टांगरपाड़ा क्रोमाइट डिपॉजिट के विकास के प्रस्ताव चार पक्षों से प्राप्त हुए थे:
>
> 1. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड;
>
> 2. जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड;
>
> 3. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड; और

4. वीज़ा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीलबंद ऑफर खुलने से पहले, जिंदल स्टील एंड पावर (ऑफर में से एक) ने अपना ऑफर वापस ले लिया। अन्य तीन पार्टियों की तकनीकी बोली 9 दिसंबर, 2002 को संबंधित पार्टियों की उपस्थिति में समिति द्वारा खोली गई। प्रत्येक पार्टी ने उसी दिन तकनीकी समिति के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत किया।"

10. यहां यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के कुछ निष्कर्ष स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नहीं हैं। जहां तक जिंदल का सवाल है, पक्षपात से संबंधित टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से बिना किसी आधार के हैं।

11. केवल इस आधार पर कि उच्च न्यायालय ने बाहरी सामग्रियों पर भरोसा किया था और निराधार निष्कर्ष पर पहुंचा है, सामान्य स्थिति में हम आदेश को रद्द कर देते और उच्च न्यायालय से मामले पर फिर से विचार करने के लिए कहते। लेकिन समय बीतने और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ई विज्ञापन 2002 में जारी किया गया था और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर, हम निम्नलिखित शर्तों पर अपीलों का निपटान करते हैं:

1. यह माना जाएगा कि तीनों पक्षों की तकनीकी बोलियाँ वैध हैं।

2. वित्तीय बोलियाँ लगभग पाँच वर्ष पहले प्रस्तुत की गई थीं, पार्टियों को तीन सप्ताह के भीतर संशोधित वित्तीय बोलियाँ प्रस्तुत करने की अनुमति देना उचित होगा।

3. आईडीसीओएल की उपयुक्त और अधिकृत समिति विज्ञापन के मापदंडों, एनआईटी और राज्य के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए तकनीकी बोलियों और वित्तीय बोलियों पर विचार करेगी।

12. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बोलियों की जांच करने वाली समिति सभी प्रासंगिक कारकों पर ध्यान देगी। मामले में इस पर विचार किया गया है। उचित और राज्य के हित में, राज्य सरकार पार्टियों के साथ बातचीत करने के लिए खुली होगी ताकि राज्य के राजस्व के सृजन और संबंधित क्षेत्रों में राज्य के समग्र विकास सहित राज्य के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जा सके।

13. चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, इसलिए राज्य सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना वांछनीय होगा कि तकनीकी बोलियां और संशोधित वित्तीय बोलियां, जैसा कि पहले निर्देश दिया गया था, तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और जून, 2008 के अंत तक सूचित निर्णय लिया जाएगा। अधिकारियों की दुर्भावना और उनके कथित पक्षपात के बारे में टिप्पणियाँ और निष्कर्ष खारिज किये जाते हैं।

14. कोस्ट के संबंध में किसी भी आदेश के बिना उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

बी.बी.बी. अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शैलेन्द्र चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।